

रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एल० एम०/13-14/94.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार, 14 अक्टूबर, 1994/22 आश्विन, 1916

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 अक्टूबर, 1994

संख्या लो० नि० (ख) 3(1) 155/94.—क्योंकि जनसाधारण ने आरोप लगाए हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नीर जिला में लिम्पो और पोवारी पुलों का निर्माण निर्वेशन (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार नहीं हुआ है और उनका निर्माण के लिए उचित प्रकार की सामग्री उपयोग नहीं की गई थी;

और क्योंकि जनता की यह मांग है कि उपर्युक्त विषय में न्यायिक जांच करवाई जाए ;

और, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में उपरोक्त आरोपों की जांच करने के लिए जो सार्वजनिक महत्व का विषय है, जांच आयोग को नियुक्त करना अधिक समीचीन होगा ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्री एम0 भार0 बौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला सत्र मण्डल, को जांच आयोग के रूप में तथा जिला क्लर्क को लिखी और पोवारि पुलों के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों के बारे में निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करने हैं :—

- (i) क्या लिखी और पोवारि के पुल निर्देशन (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार निर्मित हुए थे या नहीं ;
- (ii) क्या उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता ठीक थी या स्तर में नीचे की थी ;
- (iii) व्यक्तिगत अधिकारी पर उत्तरदायित्व नियत करना ;
- (iv) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से आवश्यक पग उठाए जाने हैं ;
- (v) लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए भविष्य में कैसी सकारात्मक कार्य योजना अपनाई जानी चाहिए ; और
- (vi) कोई अन्य विषय, जो आयोग की राय में, इस विषय से सम्बन्धित तथ्यों और वादविषयों से सुसंगत है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि जो जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा-5 की उप-धाराएं (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग के लिए लागू किए जाएं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यह भी निर्देश देते हैं कि धारा-5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा और ऐसे स्थानों की यात्रा भी कर सकेगा जो जांच को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों।

आदेश द्वारा,

भार0 के0 आनन्द,  
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Department Notification No. PBW(B & R)(B)3(1) 155/94, dated 6th October, 1994 as required under Section 348(3) of the Constitution of India].

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 6th October, 1994*

No. PBW(B & R)(B)3(1)155/94.—Whereas allegations have been levelled by members of the Public that the Leo and Powari Bridges in District Kinnaur, Himachal Pradesh were not constructed as per specifications and proper quality of material was not used for their construction ;

And whereas, there is a demand from the public to hold a judicial inquiry into the aforesaid matter ;

And whereas, Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry into the aforesaid allegations which are a matter of public importance.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section(1) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952) in consultation with the H. P. High Court is pleased to appoint Shri M. R. Chaudhary, District and Sessions Judge, Shimla Sessions Division, as Commission of Inquiry and to inquire into and report on following matters in relation to the allegations in respect of Leo and Powari Bridges in Kinnaur District and to submit his report within 3 months from the date of publication of this notification in Rajpatra H. P. :—

- (i) As to whether the Leo and Powari Bridges were constructed as per specifications or not;
- (ii) As to whether the quality of material used was proper or was below standard ?
- (iii) As to fix responsibility on individual Officer(s);
- (iv) As to what steps are considered necessary for prevention of re-occurrence of such incidents in future;
- (v) What positive action plan should be adopted for future construction activities of this nature by the Public Works Department; and
- (vi) Any other matter which in the opinion of the Commission is relevant to the facts and issues involved in the matter.

2. Further, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952) should be made applicable to the said Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions contained in sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

3. The Commission shall have its headquarter at Shimla and may also visit such places as may be necessary in furtherance of the Inquiry.

By order,

R. K. ANAND,  
Chief Secretary.